प्रेस विज्ञप्ति / Press Release **23 नवंबर / November, 2020**

राज्य में एमएसएमई पारितंत्र के विकास के लिए सिडबी ने उत्तराखण्ड सरकार के साथ समझौता ज्ञापन किया

SIDBI joins hands with Government of Uttarakhand for the development of MSME ecosystem in the State

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) के संवर्द्धन, वित्तपोषण और विकास के लिए देश की शीर्ष वित्तीय संस्था, राज्य में एमएसएमई क्षेत्र के लिए समग्र इको सिस्टम को मजबूत करने के लिए, उत्तराखंड सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) भी निष्पादित किया है।

Small Industries Development Bank of India (SIDBI), the country's apex financial institution for the promotion, financing and development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME), has entered a Memorandum of Understanding (MoU) with the Government of Uttarakhand to develop the MSME ecosystem in the State.

MoU को उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की उपस्थिति में, श्री एस ए मुरुगेसन, आईएएस, महानिदेशक, उद्योग विभाग, उत्तराखंड सरकार और श्री मनोज मित्तल, उप प्रबंध निदेशक, सिडबी द्वारा निष्पादित किया गया।

The MoU was executed in the presence of the Hon'ble Chief Minister of Uttarakhand Shri Trivendra Singh Rawat, by Shri S A Murugesan, IAS, Director General, Industries Department, Government of Uttarakhand and Shri Manoj Mittal, Deputy Managing Director, SIDBI.

इस के अंतर्गत, सिडबी उत्तराखण्ड सरकार के अधीन एक परियोजना प्रबंध इकाई स्थापित करेगा। यह परियोजना प्रबंध इकाई राज्य में एमएसएमई के संगठित विकास एवं संवृद्धि के लिए विस्तृत योजना तैयार करने, ईक्विटी सहायता, ब्याज अनुदान सहायता, दबावग्रस्त एमएसएमई संबंधी समाधान, आदि के लिए योजना (योजनाएँ) तैयार करने, संभावित /उभरते उद्यम-समूहों की मैपिंग करने तथा राज्य सरकार की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य करेगी। परियोजना प्रबंध इकाई राज्य में एमएसएमई से संबंधित कार्यक्रमों, गतिविधियों, परियोजनाओं, आदि को सरल बनाएगी और उनकी प्रभावोत्पादकता बढ़ाने एवं बाधाएँ हटाने के उद्देश्य से यदि कोई आशोधन अपेक्षित होंगे, तो उनके बारे

में सुझाव देगी। परियोजना प्रबंध इकाई दबावग्रस्त एमएसएमई इकाइयों के पुनर्वास /पुनरुज्जीवन के लिए मौजूदा संरचना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सुधार करने में उत्तराखण्ड राज्य को सहयोग देगी।

Under this, SIDBI proposes to deploy a Project Management Unit (PMU) in Government of Uttarakhand to develop a comprehensive plan for an organised development and growth of the MSMEs in the state encompassing, among other things, cluster mapping for potential/emerging clusters. The PMU will facilitate interventions, initiatives, projects etc. for MSME sector as a contribution to Atmanirbhar Bharat Abhiyan and shall suggest course corrections, if any, with the objective of enhancing efficacy and removing bottlenecks for the development of MSMEs in the state. PMU shall also support the State of Uttarakhand in making necessary interventions for rehabilitation/revival of stressed MSME units.

इस अवसर पर, सिडबी के उप प्रबंध निदेशक श्री मनोज मित्तल ने कहा "प्रयास यह है कि एमएसएमई को योग्य ऋण सुविधाएं प्रदान की जाएं, जो कुशल और प्रतिस्पर्धी होने के साथ-साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और देश को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक हो सकते हैं । इसके अलावा, सिडबी, एक बाजार निर्माता होने के नाते, क्रेडिट प्लस इनिशिएटिव के माध्यम से एमएसएमई की क्षमता बनाने में मदद करेगा और इस प्रक्रिया में, उन्हें संस्थागत ऋण के लिए पात्र बनाता है। इससे आत्मनिर्भर एमएसएमई के प्रति एक इको-प्रणाली के निर्माण के लिए पूर्ण प्रदर्शनकारी प्रभाव पैदा होगा। राज्य में बड़े पैमाने पर फार्मा उद्योग का अस्तित्व चिकित्सा उपकरण क्षेत्र की ओर एक प्राकृतिक और तार्किक रूप से आगे बढ़ने की संभावना को दर्शाता है। सिडबी द्वारा राज्य में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र की रिपोर्ट, राज्य सरकार को इस क्षेत्र के विकास के लिए पहल करने और लोकल के लिए वोकल दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में मदद करेगी। इसके अलावा, विशेषज्ञों द्वारा संचालित एक परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना भी राज्य में उद्यम इको सिस्टम को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है।"

On this occasion, Manoj Mittal, Deputy Managing Director of SIDBI said, "The endeavour is to provide credit facilities to deserving MSMEs who want to rise to the occasion in helping the country become not only self-reliant but also efficient and competitive. Further, SIDBI, being a market maker, would help build capacities of MSMEs through credit plus initiatives and in the process, make them eligible for institutional credit. This would lead to wholesome demonstrative effect for building up an ecosystem towards Atmanirbhar MSMEs. Existence of sizeable pharma industry in the State indicates possibility of a natural and logical forward linkage toward medical device sector. Report on medical device sector in the State by SIDBI, would help the State Govt undertake initiatives for development of the sector and promote Vocal for Local approach. Further, setting up of a Project Management Unit manned by experts, is also aimed at strengthening the enterprise eco system in the state."

उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने संबोधन में राज्य सरकार द्वारा राज्य में औद्योगिक विकास के लिए किए जा रहे हैं विभिन्न प्रयासों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि राज्य एमएसएमई क्षेत्र पर विशेष जोर दे रहा है और यह एमओयू राज्य में एमएसएमई ईको-सिस्टम को मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री ने चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के विकास पर रिपोर्ट के लिए सिडबी को धन्यवाद

दिया। उन्होंने यह विश्वास भी जताया कि यह एमओयू भारत सरकार के Atmanirbhar Bharat अभियान में महत्वपूर्ण योगदान होगा।

Hon'ble Chief Minister of Uttarakhand SHri Trivendra Singh Rawat in his address highlighted various initiatives being taken by his Government for industrial development. In view of his Government's special emphasis on the growth and development of MSMEs in the state, he complimented SIDBI for its report on development of medical devices sector. He also expressed confidence that the MoU with SIDBI would go a long way in implementing initiatives suggested by SIDBI as a contribution to Atmanirbhar Bharat Abhiyan of GOI.

सिडबी राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है और हाल के दिनों में राज्य सरकारों के साथ उपयुक्त हस्तक्षेप करने के लिए अपनी भागीदारी को मज़बूत कर रही है। सिडबी ने भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में एमएसएमई के लिए कई नई पहल की योजना बनाई है। इसमें से एक पहल वित्तीय और गैर-वित्तीय हस्तक्षेपों के माध्यम से नए बाजारों का पता लगाना और उनका विकास करना है। कोविद-19 महामारी और वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य के चलते स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसने, अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के बीच, चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में ध्यान केंद्रित किया है और एमएसएमई में स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं के निर्माण को sunrise sector चिह्नित किया गया है। तदनुसार, इस दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों को समपूरक करने के लिए, सिडबी ने उत्तराखंड में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के विकास की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए एक प्रतिष्ठित कंसल्टिंग फर्म, यानी अर्न्स्ट एंड यंग एलएलपी की सेवाएं लीं। अध्ययन में उत्तराखंड में इस क्षेत्र के विकास के लिए राजकोषीय और गैर-राजकोषीय और अल्पकालिक और दीर्घकालिक रणनीतियों और रोड मैप की सिफारिश की गई है। माननीय मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र के विकास पर सिडबी की रिपोर्ट का अनावरण किया।

SIDBI has been deepening its engagements with State Governments in the recent past and working closely with them to undertake suitable interventions. SIDBI has planned number of new initiatives for MSMEs towards Atmanirbhar Bharat Abhiyan of Government of India. One among such initiatives is to explore and develop new markets through financial and non-financial interventions. Ongoing COVID-19 pandemic and global geo-political scenario has led to increased focus on self-reliance in health & health care segment. This has, among other industrial sectors, put the spotlight on medical devices sector and creation of indigenous manufacturing capabilities is a sunrise area for MSMEs. Accordingly, to complement the efforts of State Government in this direction, SIDBI engaged the services of a reputed consulting firm, i.e. Ernst & Young LLP to study scope and possibilities of development of medical device sector in Uttarakhand. The study recommends fiscal and non-fiscal as well as short-term and long-term strategies and road map for the development of this sector in Uttarakhand. Hon'ble Chief Minister of Uttarakhand, Shri Trivendra Singh Rawat unveiled the report of SIDBI on development of medical devices sector in Uttarakhand.

इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष श्री पंकज गुप्ता ने सिडबी की इस पहल की सराहना की। उन्होंने उत्तराखंड सरकार से चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में सिडबी की रिपोर्ट में सिफारिशों को जल्द से जल्द लागू करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लगभग 35000 करोड़ रुपये के आयात को रोका जा सकता है।

Shri Pankaj Gupta, President of Industries Association of Uttarakhand lauded this coming together of the State of Uttarakhand and SIDBI and SIDBI's initiative to bring out the report on medical devices. He added that self-reliance in this sector could save imports worth around Rs. 35,000 crore to the exchequer.

सिडबी के बारे में : 1990 में अपने गठन के बाद से, सिडबी अपने एकीकृत, अभिनव और समावेशी दृष्टिकोण के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों के नागरिकों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। चाहे वे पारंपरिक, छोटे घरेलू उद्यमी हों, पिरामिड के सबसे निचले स्तर के उद्यमी हों, या फिर उच्च-स्तरीय ज्ञान आधारित उद्यमी हों, सिडबी ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के जीवन को विभिन्न ऋणों तथा विकास कार्यों के माध्यम से प्रभावित किया है।

अधिक जानने के लिए, देखें : https://www.sidbi.in

About SIDBI: Since its formation in 1990, SIDBI has been impacting the lives of citizens across various strata of the society through its integrated, innovative and inclusive approach. Be it traditional, domestic small entrepreneurs, bottom-of-the-pyramid entrepreneurs, to high-end knowledge-based entrepreneurs, SIDBI has directly or indirectly touched the lives of Micro and Small Enterprises (MSEs) through various credit and developmental engagements.

To know more, check out: https://www.sidbi.in